भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 815
जिसका उत्तर मंगलवार, 01 मार्च, 2016 को दिया जाना है

बिजली चालित वाहन

815. श्री शिवकुमार उदासि:
क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो देश में इलेक्ट्रिक कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों का विनिर्माण कर रही है;

(ख) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक कारों, स्कूटरों, साइकिलों आदि के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नीतिगत ढांचा बनाने एवं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी० एम० सिद्देश्वर)

(क): भारी उद्योग विभाग के साथ विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा किए गए पंजीकरण के अनुसार, निम्नलिखित कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक और/अथवा हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण करती हैं:

i. महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड
ii. इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड
iii. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
iv. हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लि.
v. टोयोटा किरलोसकर मोटर प्रा. लि.
vi. लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज
vii. एम्पेयर व्हीकल्स प्रा. लि.
viii. एवन साइकल्स लिमिटेड
ix. क्रिस मोटर्स
x. अजन्ता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड

(ख) और (ग): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और तत्पश्चात् 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को अनावृत्त किया। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इन वाहनों के धारणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु और मिशन की जांच के लिए, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने 01 अप्रैल, 2015 से शुरू करके आरंभिक दो वर्ष की अवधि के लिए फेम-इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम का मुख्य प्रयोजन देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

****